

MPSE 007 (PART-1)

SOCIAL MOVEMENTS AND POLITICS IN INDIA भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति

Important Questions & Repeated Topics
For both Hindi and English medium students

Topic 1

Analyze the politics based reservation in india.

Historical Background

The reservation system in India has its roots in the British colonial era when affirmative action policies were introduced to uplift marginalized communities. Post-independence, the Indian Constitution institutionalized reservations to address historical injustices and social inequalities faced by Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs).

भारत में आरक्षण प्रणाली की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में हैं जब हाशिए पर रहने वाले समुदायों को ऊपर उठाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा सामना की गई ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने के लिए आरक्षण को संस्थागत रूप दिया।

Purpose of Reservation

The primary purpose of reservation is to promote social justice by providing opportunities in education, employment, and political representation to historically disadvantaged groups. It aims to create a level playing field and integrate these communities into the mainstream.

आरक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर प्रदान करके सामाजिक न्याय को

बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना और इन समुदायों को मुख्यधारा में शामिल करना है।

Political Implications

Reservation policies have significant political implications in India. They are often a key issue in elections, with political parties promising increased quotas to garner support from marginalized communities. This has led to a politicization of the reservation system.

भारत में आरक्षण नीतियों के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं। चुनावों में वे अक्सर एक प्रमुख मुद्दा होते हैं, जिसमें राजनीतिक दल हाशिए पर रहने वाले समुदायों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बढ़े हुए कोटा का वादा करते हैं। इससे आरक्षण प्रणाली का राजनीतिकरण हुआ है।

Controversies and Challenges

The reservation system faces several controversies and challenges. Critics argue that it perpetuates caste divisions, promotes reverse discrimination, and sometimes benefits the more affluent among the reserved categories. Additionally, there are debates about extending reservations to economically weaker sections (EWS) irrespective of caste.

आरक्षण प्रणाली को कई विवादों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आलोचकों का तर्क है कि यह जाति विभाजन को बनाए रखता है, प्रतिकूल भेदभाव को बढ़ावा देता है, और कभी-कभी आरक्षित श्रेणियों में अधिक समृद्ध लोगों को लाभ पहुँचाता है। इसके अतिरिक्त, जाति की परवाह किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तक आरक्षण बढ़ाने पर बहस होती है।

Judicial Interventions

The judiciary in India has played a crucial role in shaping reservation policies. The Supreme Court's landmark decisions, such as the Indra Sawhney case (1992), set the 50% cap on reservations and introduced the concept of creamy layer exclusion in OBC reservations. These rulings aim to ensure that the benefits reach the truly needy.

भारत में न्यायपालिका ने आरक्षण नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय, जैसे इंदिरा साहनी मामला (1992), ने आरक्षण पर 50% की सीमा निर्धारित की और ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर बहिष्करण की अवधारणा पेश की। ये फैसले यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं कि लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे।

Evolving Reservation Policies

Reservation policies in India continue to evolve. Recent amendments, such as the introduction of the EWS quota, reflect changing societal needs and demands. Policymakers face the challenge of balancing social justice with meritocracy and ensuring that reservations serve their intended purpose without fostering new inequalities.

भारत में आरक्षण नीतियाँ विकसित होती रहती हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा की शुरुआत जैसे हालिया संशोधन, बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और मांगों को दर्शाते हैं। नीति-निर्माताओं के सामने सामाजिक न्याय और योग्यता के साथ संतुलन बनाने और यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि आरक्षण अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करे बिना नई असमानताओं को बढ़ावा दिए।

Topic 2

How and why caste factors are significant for Indian reforms.

1. Social Inclusion and Equity

The caste system has historically marginalized certain groups in Indian society. Reforms targeting caste inequities aim to promote social inclusion and equity, ensuring that marginalized communities have equal access to resources, opportunities, and rights.

सामाजिक समावेशन और समानता

जाति व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में कुछ समूहों को हाशिए पर रखा है। जातिगत असमानताओं को लक्षित करने वाले सुधार सामाजिक समावेशन और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को संसाधनों, अवसरों और अधिकारों तक समान पहुंच प्राप्त हो।

2. Educational Reforms

Caste-based reservations in educational institutions are designed to uplift underprivileged communities. These reforms help ensure that students from lower castes can access quality education, which is crucial for breaking the cycle of poverty and social discrimination.

शैक्षिक सुधार

शैक्षिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण का उद्देश्य वंचित समुदायों को ऊपर उठाना है। ये सुधार यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि निचली जातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, जो गरीबी और सामाजिक भेदभाव के चक्र को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।

3. Economic Empowerment

Caste factors are significant in economic reforms aimed at reducing poverty and promoting economic empowerment among marginalized communities. Policies such as affirmative action in employment and entrepreneurship support are critical for improving the economic status of lower-caste individuals.

आर्थिक सशक्तिकरण

हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच गरीबी कम करने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों में जाति के कारक महत्वपूर्ण हैं। रोजगार और उद्यमिता समर्थन में सकारात्मक कार्रवाई जैसी नीतियां निम्न जाति के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

4. Political Representation

Ensuring political representation for lower-caste groups through reservations in government bodies is crucial for inclusive governance. This allows marginalized communities to have a voice in decision-making processes and policies that affect their lives.

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

सरकारी निकायों में आरक्षण के माध्यम से निम्न जाति समूहों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना समावेशी शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नीतियों में अपनी आवाज उठाने की अनुमति देता है जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।

5. Legal Reforms

Caste factors influence legal reforms aimed at protecting the rights of marginalized communities. Anti-discrimination laws, protection against caste-based violence, and legal aid for lower-caste individuals are essential for promoting justice and equality.

कानूनी सुधार

जातिगत कारक वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कानूनी सुधारों को प्रभावित करते हैं। भेदभाव विरोधी कानून, जाति आधारित हिंसा से सुरक्षा और निम्न जाति के व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

Topic 3

Agrarian movements in India

1. Tebhaga Movement (1946-47)

The Tebhaga Movement was a significant agrarian struggle in Bengal, where sharecroppers demanded two-thirds of the produce from their landlords instead of the traditional one-half. This movement was crucial in highlighting the plight of the sharecroppers and led to significant changes in agrarian relations in Bengal.

तेभागा आंदोलन (1946-47)

तेभागा आंदोलन बंगाल में एक महत्वपूर्ण कृषक संघर्ष था, जहाँ बटाईदारों ने अपने जमींदारों से परंपरागत आधे के बजाय उपज का दो-तिहाई हिस्सा माँगा। इस आंदोलन ने बटाईदारों की दुर्दशा को उजागर किया और बंगाल में कृषि संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए।

2. Telangana Rebellion (1946-51)

The Telangana Rebellion was a peasant uprising against the feudal system and oppressive landlordism in the Hyderabad state. It aimed

at ending the exploitation of peasants by landlords and led to significant socio-economic reforms in the region.

तेलंगाना विद्रोह (1946-51)

तेलंगाना विद्रोह हैदराबाद राज्य में सामंती व्यवस्था और जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। इसका उद्देश्य जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण को समाप्त करना था और इसने क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सुधार लाए।

3. Naxalite Movement (1967 onwards)

Originating in the Naxalbari village of West Bengal, the Naxalite Movement is an armed struggle led by Maoist groups advocating for agrarian rights, land redistribution, and social justice. This movement has had a significant impact on India's political and social landscape.

नक्सलवादी आंदोलन (1967 से)

पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से उत्पन्न, नक्सलवादी आंदोलन एक सशस्त्र संघर्ष है जो माओवादी समूहों द्वारा कृषि अधिकारों, भूमि पुनर्वितरण और सामाजिक न्याय की वकालत करता है। इस आंदोलन ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

4. Bhartiya Kisan Union (BKU) Movements (1980s onwards)

The BKU movements, particularly in northern India, have focused on various issues such as fair prices for crops, reduction in input costs, and better infrastructure. These movements have significantly influenced agricultural policies in India.

भारतीय किसान यूनियन (BKU) आंदोलन (1980 के दशक से)

विशेष रूप से उत्तरी भारत में BKU आंदोलनों ने फसलों के लिए उचित मूल्य, इनपुट लागत में कमी और बेहतर बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। इन आंदोलनों ने भारत में कृषि नीतियों को काफी हद तक प्रभावित किया है।

5. Shetkari Sanghatana (1980s onwards)

Founded by Sharad Joshi in Maharashtra, the Shetkari Sanghatana movement advocates for the rights of farmers, emphasizing free-

market policies and deregulation of agriculture. This movement has been pivotal in voicing the demands of farmers in Maharashtra.

शेतकरी संगठन (1980 के दशक से)

महाराष्ट्र में शरद जोशी द्वारा स्थापित, शेतकरी संगठन आंदोलन किसानों के अधिकारों की वकालत करता है, जिसमें मुक्त बाजार नीतियों और कृषि के विनियमन को समाप्त करने पर जोर दिया गया है। यह आंदोलन महाराष्ट्र में किसानों की मांगों को उठाने में महत्वपूर्ण रहा है।

6. 2020-2021 Farmers' Protests

These protests were against three farm laws passed by the Indian government, which farmers feared would dismantle the minimum support price system and corporatize agriculture. The protests gained significant national and international attention and resulted in the eventual repeal of the laws.

2020-2021 किसान आंदोलन

ये आंदोलन भारतीय सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ थे, जिन्हें किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करने और कृषि का निजीकरण करने की आशंका जताई थी। इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया और अंततः कानूनों को निरस्त कर दिया गया।

END OF 1ST PART

**Subscribe the channel for similar videos of various topics..
Like&Comment....**